See that you follow guidelines and secondly, *See* to it and guide people that they also follow the guidelines issued by the Central and State Governments from time to time. The vaccination process is on. I request all the Members and their family members who are eligible, to take vaccination this weekend, in their respective places and *See* to it that the eligible people also volunteer to take the vaccine.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Need to implement the recharge plan for Jawai Dam in Western Rajasthan

श्री ओम प्रकाश माथुर (राजस्थान): सभापति महोदय, मैं पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े बांध, जवाई बांध के पुनर्भरण के विषय में अपनी बात रखना चाहता हूँ। यह बांध 1957 में बन कर तैयार हुआ और 1957 के बाद हम लोगों ने प्रयत्न करके उसको fulfill करने के लिए और छोटे डैम बनाए, लेकिन फिर भी इतने वर्षों में यह मात्र आठ से दस बार भरा है। इससे 40 गाँवों की लगभग 40 हज़ार हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की इरिगेशन हो रही है। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने सरकार बनते ही जल शक्ति मंत्रालय के नाम से अलग मंत्रालय बनाया और हिन्दुस्तान के प्रत्येक नागरिक को पीने का शुद्ध पानी मिले, इसकी चिंता करके उसके लिए बहुत बड़ा बजट भी allocate किया। इस बांध के माध्यम से drinking water के लिए हम day-to-day गाँवों की संख्या बढ़ाते गए, लेकिन इसके पुनर्भरण की ओर आज तक ध्यान नहीं दिया। 2017 में इसकी डीपीआर भी बनी।

महोदय, साबरतमती का जो वेस्ट पानी है, हर साल कम से कम जो दस गुना पानी वेस्ट जा रहा है, उस पानी के लिए हमने माँग की कि वह पानी जवाई बांध में लाया जाए। उसकी डीपीआर भी लगभग बन गई थी और 12 करोड़ रुपए भी sanction हो गए थे, लेकिन आज तक उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही कहना है कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में इसकी चिंता की जाए, क्योंकि यह जवाई बांध हमारे पश्चिमी राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे मारवाड़ की लाइफलाइन है। इसका निर्माण आज़ादी से पहले शुरू हुआ और सन् 1957 में यह पूरा बन गया। महोदय, हम इससे गाँव तो जोड़ते जा रहे हैं, अब लगभग 40 गाँवों की दस लाख से ज्यादा आबादी को इससे ड्रिंकिंग वॉटर मिल रहा है। अभी-अभी स्टेट गवर्नमेंट और केंद्रीय गवर्नमेंट के सहयोग से जल शक्ति मंत्रालय ने इसमें 500 गाँव और जोड़े, लेकिन किसानों की धरती आज भी सूखी रह जाती है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूँगा कि जवाई पुनर्भरण की योजना को जितना जल्दी हो सके, पूरा किया जाए। यह बड़ी योजना है, 6,000 करोड़ से ज्यादा की योजना है। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि इस योजना की चिंता करके इस काम को शुरू करें।

श्री सभापति : जिन्हें associate करना है, वे अपने नाम भेज दीजिए।

SHRI Y.S. CHOWDARY (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself with the submission made by Shri Mathur.

SHRI ASHWINI VAISHNAW (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by Shri Mathur.

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान) : सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान) : सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

डा. भागवत कराड़ (महाराष्ट्र) : सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री सैयद जफर इस्लाम (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by Shri Mathur.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by Shri Mathur.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by Shri Mathur.

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by Shri Mathur.

Need to ensure proper data analysis for OBCs in Census 2021

श्री राजीव सातव (महाराष्ट्र) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन और सरकार का ध्यान दिलाने के लिए परमिशन दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, ओबीसी जनगणना की माँग बहुत सालों से की जा रही है। मुझे याद है कि जब लोक सभा में गोपीनाथ मुंडे जी थे, उन्होंने भी उस वक्त इस माँग को बहुत ताकत से उठाया था। जब सरकार जानवरों की गणना कर सकती है, पेड़ों की गणना कर सकती है, तो समाज के इस महत्वपूर्ण घटक, ओबीसी की क्यों नहीं कर सकती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओबीसी की जनगणना के विषय पर सरकार ने 2018 में भी आश्वस्त किया था कि हम ओबीसी की जनगणना करेंगे। 2019 में सरकार ने इसे फिर से कहा था कि हम इस जनगणना की दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अभी देखा गया कि उसमें से ओबीसी का कॉलम ही हटा दिया गया है। अगर हमें ओबीसीज़ को सही लाभ देना है, तो उनकी जनगणना होने के बाद ही सही मायने में पता चल सकता है कि उन्हें कितना लाभ मिल रहा है, कितना लाभ नहीं मिल रहा है? महोदय, इस विषय पर सरकार भी पहल कर सकती है, इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि ओबीसी की जनगणना के विषय पर सरकार को तुरंत सोचना चाहिए।

श्री सभापति : जिन्हें associate करना है, वे अपने नाम भेजें।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) : सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़) : सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूँ।

श्री नीरज डांगी (राजस्थान) : सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्रीमती फूलो देवी नेतम (छत्तीसगढ़) : सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूँ।